राजस्थान अपार संभावनाओं का प्रदेश, निवेशक राज्य की विकास यात्रा में सहभागी बनें : मुख्यमंत्री

बिजली-पानी-रोजगार क्षेत्र में हमने लिए हैं अभूतपूर्व निर्णय : भजनलाल शर्मा

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार राजस्थान को केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि समृद्ध, सशक्त और सर्वापरि राज्य बनाने की प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। उन्होंने उद्यिमयों से आव्हान किया कि उद्यमी अधिक से अधिक निवेश कर राज्य की विकास यात्रा में सहभागी बनें। शर्मा गुरूवार को जयपुर में इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2025 को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा तथा व्यापारिक दृष्टि से अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है। राइजिंग राजस्थान समिट के आयोजन से राज्य सरकार को 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, इनमें से 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर धरातल पर काम शुरू हो गया है।

उन्होंने कहा कि उद्योगों को अधिक सुगम बनाने के लिए राज्य में राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान मिनरल पॉलिसी, रीको प्रत्यक्ष आवंटन नीति, डेटा सेंटर नीति, वस्त्र एवं परिधान नीति, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति जैसी नीतियां जारी की गई। शर्मा ने कहा कि राजस्थान ने खनिज ब्लॉकों की नीलामी में देशभर में नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

देश के कुल खनिज ब्लॉक आवंटन का 20 प्रतिशत अकेले राजस्थान से हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने विजन डॉक्यूमेंट-2047 को मंजूरी दी है। यह केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि राजस्थान के सुनहरे भविष्य का खाका है। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक राजस्थान 350 बिलियन डॉलर और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बने। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 सौर परियोजनाओं को मंजूरी, नई भूमि आवंटन नीति, पंच गौरव जैसे नवाचारों एवं निर्णयों से ऊर्जा एवं उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए निरंतर निर्णय ले रही है। जोधपुर-पाली औद्योगिक गलियारा, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो 19 हजार करोड रुपए की लागत से बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 50,000 प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा वस्त्र, कृषि, इंजीनियरिंग और ऑटो क्लस्टर उद्योगों पर केंद्रित यह परियोजना राजस्थान को औद्योगिक मानचित्र पर नया स्थान दिलाएगी।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 जारी की गई है, जो 2030 तक प्रदेश के अक्षय ऊर्जा उत्पादन को 125 गीगावाट के स्तर तक ले जाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है तथा 2027 तक सभी किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए 'एक पेड़ मां के नाम अभियान' से प्रेरणा लेते हुए 'हरियालो राजस्थान' की शुरुआत की है। अभियान के तहत 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है तथा अब तक हम 17 करोड़ से अधिक पौधे लगा चुके है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में असीमित अवसरों के साथ प्राकृतिक संसाधन एवं कुशल मानव संसाधन मौजूद है।

राज्य सरकार ने पिछले डेढ़ साल में पानी, बिजली, बुनियादी ढांचे और प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए अनेक निर्णय लिए हैं। पेयजल और सिंचाई की समस्या के स्थायी समाधान के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, माही बांध योजना सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं। साथ ही, हमने 5 साल के कार्यकाल में युवाओं को 4 लाख सरकारी और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण, 1 हजार 300 गांवों को डामर सड़कों से जोड़ना, मिसिंग लिंक रोड का निर्माण, जयपुर एयरपोर्ट का विस्तार सहित विभिन्न कार्यों से राज्य में विकास के नए मानदंड स्थापित किए जा रहे हैं।

ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऊर्जा के क्षेत्र में प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। अक्षय ऊर्जा तथा ट्रांसमिशन तंत्र को विकसित करने से इस क्षेत्र में बहुत तेजी से कार्य हो रहा है। हमारा संकल्प है कि हम किसान को 2027 तक दिन में बिजली देंगे।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् के सदस्य प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा कि राजस्थान सरकार सुशासन का पर्याय बन चुकी है। वर्तमान सरकार जिम्मेदारी, जवाबदेही और उत्तरदायित्व के साथ कार्य कर रही है। यह पहला ऐसा राज्य है, जिसने अपने कार्यकाल के शुरूआत में ही निवेश समिट का आयोजन किया, साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा सतत् विकास को बढ़ावा देते हुए हरियालो राजस्थान, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जैसे नवाचार भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार चार गुना शक्ति के साथ राजस्थान को आगे ले जा रही है। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी अडानी गैस सुरेश पी. मंगलानी, निदेशक एवं सहसंस्थापक एस.ए.ई.एल. इंडस्ट्रीज लि. सुखबीर आवला सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने समिट में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग अजिताभ शर्मा सहित बड़ी संख्या में उद्यमी और गणमान्य मौजूद रहे।

> ■ "राइजिंग राजस्थान समिट में राज्य सरकार को 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, इनमें से 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर धरातल पर काम शुरू हो गया है।"

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को जयपुर में इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2025 को संबोधित किया।

'नेता प्रतिपक्ष जूली की सहमति से 29 के बजाय 28 को रखी सर्वदलीय बैठक, फिर भी कांग्रेस ने किया बहिष्कार'

विधानसभा के मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्पीकर वासुदेव देवनानी ने गुरूवार को बुलाई थी यह सर्वदलीय बैठक

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। विधानसभा का मानसून सत्र सुचारू रूप से चलने के लिए गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सर्दलीय बैठक बुलाई थी। कांग्रेस ने यह कहते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया कि यहां एक तरफा फैसला लिए जाते हैं।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक 2 सितंबर को होगी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे।

वहीं दूसरी ओर बैठक के बहिष्कार पर सत्ता पक्ष ने कहा कि, विपक्षी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। बहिष्कार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि सर्वदलीय बैठक से पहले सभी पक्षों से सहमती ली जाती है। आज की डेट टीकाराम जूली से पूछकर ही तय की गई थी। वे 29 अगस्त को आने में असमर्थ थे, इसलिए जूली के कहने पर 28 अगस्त डेट तय की गई। अचानक उन्होंने सूचना दी कि वे और उनके सचेतक भी नहीं आएंगे। ऐसा करना मैदान छोड़ने वाली बात हुई। गर्ग ने कहा कि जानबूझकर बहिष्कार किया है। इसके कारण अभी तक हमको समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की आपस की लडाई, डोटासरा वर्सेस जूली की वजह से ये सब कुछ हो रहा है।

गर्ग ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी निंदा करते है। जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विधानसभा को लेकर शुरुआत से ही भाजपा सरकार की मंशा अच्छी नहीं रही है। विधानसभा अध्यक्ष चाह रहे हैं कि सत्र लम्बा चले, लेकिन सरकार चाह रही है कि कुछ दिन में ही विधानसभा सत्र खत्म हो जाए, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित न हो सके। विधानसभा में भी कई वाकये ऐसे हुए हैं जो एक पक्षीय रहे। हमारे विधायक नरेन्द्र बुढ़ानिया को विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष बनाया, लेकिन अचानक से उन्हें कुछ दिन में ही हटा दिया गया। इतने वरिष्ठ सदस्य के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। जूली ने कहा कि

विधानसभा में सवालों के जवाब पहले जनता के लिए पोर्टल पर अपलोड होते थे, वो इस बार अपलोड नहीं किए गए। क्या सरकार को कोई डर है? जूली ने कहा कि इसी प्रकार जिलों में हमारे प्रधानों, प्रमुखों, चेरयमैनों को चुन-चुनकर हटाया जा रहा है। सरकार के एक विधायक ने जनता के बीच कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में सभी प्रधानों को हटाकर भाजपा के प्रधान बनाए हैं। यानी इनका लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। यही कारण है कि संवैधानिक बाध्यताओं के बावजूद राज्य में पंचायतीराज एवं नगरीय निकाय के चुनाव भी सरकार नहीं करवा रही और हाईकोर्ट से स्टे लेकर आ रही है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमारी सरकार के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मई 2020 में सभी 200 विधायकों और 25 सांसदों की बैठक लेकर उनकी बात सुनी थी। यहां केवल भाजपा विधायकों, सांसदों और जिनको जनता ने नकार दिया उन हारे हुए प्रत्याशियों से बात की जा रही है, लेकिन विपक्ष की आवाज को नहीं सुना जा रहा है। ऐसी एकतरफा अप्रोच के कारण आज कांग्रेस पार्टी ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। हम सदन की पहले दिन की बैठक में भाग लेंगे। 2 सितंबर को हमारे विधायक दल की बैठक है जिसमें हमारे प्रभारी, प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री समेत सभी वरिष्ठ नेता होंगे और वहां आगे का निर्णय लिया जाएगा।

> ■ सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि, "नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अचानक सूचना दी कि वे और उनके सचेतक बैठक में नहीं आएंगे। ऐसा करना मैदान छोड़ने वाली बात हुई। मुझे लगता है कि कांग्रेस की आपस की लडाई, "डोटासरा वर्सेस जूली" की वजह से ये सब कुछ हो रहा है।"

'आर.जी.एच.एस. में 350 अस्पतालों ने जारी रखीं सेवाएं, 38 हजार रोगियों को मिला उपचार'

जयपुर (कासं)। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा है कि राज्य सरकार राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम के सुचारू संचालन के लिए प्रतिबद्ध है। रोगियों को योजना का लाभ लेने में किसी तरह की बाधा नहीं आए, इस दिशा में हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजना में जरूरी बदलाव कर इसे बेहतर बनाया जाए, ताकि लाभार्थियों को सुगमता से उपचार मिले। इसके लिए फुल प्रूफ सिस्टम विकसित किया जा रहा है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि गुरूवार को भी प्रदेश के ज्यादातर निजी अस्पतालों में आरजीएचएस योजना के तहत सुचारू रूप से उपचार मिला। उन्होंने बताया कि करीब 350 अस्पतालों में ओपीडी, डे केयर एवं आईपीडी में रोगियों ने उपचार प्राप्त किया। प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध सभी अस्पतालों में आरजीएचएस योजना के तहत उपचार मिल रहा है।

राठौड़ ने कहा कि निजी अस्पतालों के साथ-साथ राजकीय चिकित्सा संस्थानों में भी योजना के तहत उपचार के लिए सभी माकूल इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं, ताकि जहां भी निजी अस्पतालों में उपचार बंद हों, वहां राजकीय चिकित्सा संस्थानों में रोगी सुगमता से उपचार प्राप्त कर सकें। विगत 4 दिवस में करीब 38 हजार रोगियों ने आरजीएचएस योजना के तहत उपचार प्राप्त किया है।

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजीलाल अटल ने बताया कि जिन अस्पतालों ने उपचार बंद कर रखा है, उनके प्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद जारी है।

हमारा प्रयास है कि सभी अस्पताल योजना के तहत सेवाएं उपलब्ध करवाएं। निजी अस्पतालों व सभी हितधारकों से चर्चा कर योजना में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। गड़बड़ी पर अंकुश लगाकर योजना का निर्बाध संचालन विभाग की प्राथमिकता है।

> ■ राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजीलाल अटल का कहना है कि, "जिन अस्पतालों ने आर.जी.एच.एस. में उपचार बंद कर रखा है, उनके प्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद जारी है। हमारा प्रयास है कि सभी अस्पताल योजना के तहत सेवाएं उपलब्ध करवाएं।"

जेल में फिर मिला मोबाइल और सिम

जयपुर। राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल में मोबाइल और सिम मिलने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। अब एक बार फिर जेल में मोबाइल और सिम मिलने से हडकंप मच गया। जेल में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान मोबाइल और सिम लावारिस हालत में मिले हैं। इस संबंध में जेल प्रशासन की ओर से लालकोठी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया हैं। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। थानाधिकारी बन्नालाल ने जेल अधीक्षक की ओर से मामला दर्ज करवाया है कि 27 अगस्त को जेल प्रशासन की ओर से सघन तलाशी अभियान चलाया गया था। इस दौरान दो नंबर वार्ड के बैरक नंबर 2 में टॉयलेट के पास एक सिल्वर कलर का छोटा कीपैड मोबाइल और सिम मिली है। इस पर जेल कर्मचारियों ने उच्चाधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दीं।

बीकानेर के नाथूसरबास निवासी 3 वर्षीया निधि नागल पुत्री मधुसूदन नागल ने अपनी मां के साथ इको-फ्रेंडली मिट्टी का गणपति बनाया है। अपने गणपति के साथ निधि।

उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया

जयपुर। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एसआई भर्ती परीक्षा - 2021 को रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। क्योंकि करीब 500 लोग नकल माफिया के साथ सौदा कर परीक्षा में पास हुए। ये लोग पुलिस जैसे संवेदनशील विभाग में एसआई बनकर जनता के साथ क्या न्याय करते एवं कैसे कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग देते। मैंने पहले दिन से ही एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग की थी, क्योंकि मेरे पास एसआई पेपर लीक होने के पक्के सबूत थे। मैंने पूर्ववर्ती सरकार के समय एसओजी को ये सभी सबूत दिए। मैंने जैसे ही सबूत दिए वे सही निकलते गये, जिसके लिए आंदोलन किए, लेकिन पूर्व सरकार की नकल माफिया से सांठगांठ थी।

शाही ठाठ-बाट के साथ जयपुर भ्रमण पर निकले गणेशजी महाराज

मोतीडूंगरी मंदिर से शुरू हुई शोभायात्रा में 50 से अधिक झांकियां शामिल हुईं

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर से श्री गणेश जन्मोत्सव के अंतर्गत गज पूजन के साथ 38वीं शोभायात्रा की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आरती कर शोभायात्रा को रवाना किया। यह पारंपरिक शोभायात्रा गढ़ गणेशजी मंदिर तक निकाली जाती है।

शोभायात्रा में चित्रस्वरूप भगवान श्री गणेश की विधिवत रूप से पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मोती डूंगरी श्री गणेश मंदिर में दर्शन भी किए। जहां महंत कैलाश शर्मा ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं से आत्मीयता के साथ मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस अवसर पर सांसद मंजू शर्मा सहित विभिन्न जनप्रतिनिधिगण और गणमान्यजन उपस्थित रहे।

शोभायात्रा में आगे ध्वज लिए हाथी को रवाना किया गया। इसके साथ ही शोभायात्रा में 4 हाथी, 11 ऊंट और 21 घोड़े लवाजमे में शामिल हुए । शोभायात्रा की थीम ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित थी। इसी के साथ शोभायात्रा में 50 से अधिक झांकियों का संचालन किया गया। भव्य शोभायात्रा में राम मंदिर में गणेशजी का तांडव नृत्य, रामलला के दर्शन, राम-रावण युद्ध, महाभारत का लेखन, शिव-पार्वती के प्रसंग, माता वैष्णो देवी दरबार की झांकी बनाई गई। यह शोभायात्रा गुरुवार शाम चार बजे मोती डूंगरी से रवाना हुई जो मोती डूंगरी रोड, जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार से गणगौरी बाजार होते हुए ब्रह्मपुरी से नाहरगढ की पहाड़ी पर विराजमान गढ़ गणेश मंदिर पर समाप्त हुई। इस शोभायात्रा के साथ मोती डूंगरी मंदिर के नौ दिन के गणेश जन्मोत्सव का समापन हुआ।

शोभायात्रा के संयोजक भानु प्रताप ने बताया कि गुलाबी नगरी की यह परंपरा हर साल भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहती है। इस बार शोभायात्रा में भक्तों को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दोनों अनुभव मिलता है। शोभायात्रा में सबसे आगे हाथी पर गामा पहलवान निशान ध्वज लेकर मौजूद रहे। इसके पीछे ऊंट-घोड़े और बैंड बाजे के साथ चलते रहे।

इस बार शोभायात्रा में 50 से अधिक झांकियां शामिल हुईं। पारंपरिक हाथी-घोड़े-ऊंट के लवाजमे से लेकर धार्मिक, ऐतिहासिक और समकालीन प्रसंगों को दर्शाती झांकियां सजाई गईं। इसमें ऑपरेशन सिंदूर और एस-400 मिसाइल की झांकी भी शामिल हुई। झांकियों में भगवान गणेश के विभिन्न स्वरूपों के साथ-साथ अयोध्या राम मंदिर में रामलला के दर्शन, राम-रावण युद्ध, महाभारत का लेखन, शिव-पार्वती के प्रसंग, माता वैष्णो देवी दरबार, महाकाल, छत्रपति शंभाजी महाराज, केदारनाथ धाम, शेखावाटी की सांस्कृतिक झलक और संत परंपराओं को भी प्रदर्शित किया गया। मंदिर समिति के अनुसार, भगवान गणेश की झांकियां स्वचालित तकनीक से भी सजाई गई।

इनमें गणेशजी का तांडव नृत्य, रिद्धि-सिद्धि संग नृत्य, मूषक पर सवारी, महाकाल रूप, और मोबाइल की लत से दूर रहने का संदेश जैसी झलकियां प्रमुख रहीं। एक झांकी में भगवान शंकर की पीठ पर गणेश जी सवारी करते हुए दिखाए गए। काशी की प्रसिद्ध मसाने की होली की झांकी भी सजाई गई। गणेश जी के महाभारत लिखने की झांकी सजाई गई। इस झांकी में आदि शिव को भी दिखाया गया है। शोभायात्रा समिति के संयोजक भानु प्रताप ने बताया- इस बार बहुत विशेष झांकियों का आयोजन किया गया है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर की झांकी और मिसाइल एस 400 भी शामिल है।

यह वही मिसाइल है, जिसने पाकिस्तान में जाकर तबाही मचाई। इसके अलावा राजस्थान की संस्कृति को दिखाती हुई झांकी भी शामिल की गई है। इसमें त्रिपोलिया गेट से निकलने वाली तीज माता की सवारी की झांकी भी शामिल है।

> ■ ऑपरेशन सिंदूर एस 400 मिसाइल की तर्ज पर निकाली गई शोभायात्रा रही आकर्षण का केन्द्र

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना के बाद शोभायात्रा को रवाना किया। इस दौरान "ऑपरेशन सिंदूर" थीम पर सजाई गई झांकी आकर्षण का विशेष केन्द्र रही।

जवाहर कला केन्द्र में "चित्रायण: जर्नी थ्रू आर्ट" का शुभारंभ

जयपुर। जयपुर के जवाहर कला केन्द्र स्थित अलंकार आर्ट गैलरी में संयुक्त कला प्रदर्शनी "चित्रायण: जर्नी थ्रू आर्ट" का भव्य शुभारंभ हुआ। यह प्रदर्शनी चार प्रतिभाशाली महिला कलाकारों - निधि चौधरी, निकिता टाटेर, पारिधि जैन और शगुन अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है। प्रदर्शनी का उद्घाटन वन मंत्री संजय शर्मा द्वारा किया गया।

इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्तियों और कला प्रेमियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यह प्रदर्शनी राजस्थान की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी हुई है, साथ ही विश्वभर की यात्राओं से मिली प्रेरणाओं को भी दर्शाती है।

शगुन अग्रवाल, जो मनोविज्ञान में प्रशिक्षित हैं और बचपन से कला से जुड़ी रही हैं, अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से बदलते मानसिक परिदृश्यों को अभिव्यक्त करती हैं। उनकी कला श्रृंखला ए जर्नी इन्वॉर्ड आत्मान्वेषण और आत्मसंवाद की गहरी झलक देती है। शगुन अपने पॉडकास्ट 'शेरदिल्ली' के जरिये भी व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभवों को जोड़ने का कार्य करती हैं। यह प्रदर्शनी 31 अगस्त 2025 तक प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक कला प्रेमियों के लिए खुली रहेगी।

> ■ चार प्रतिभाशाली महिला कलाकारों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन

चार प्रतिभाशाली महिला कलाकारों निधि चौधरी, निकिता टाटेर, पारिधि जैन और शगुन अग्रवाल की ओर से जवाहर कला केन्द्र में संयुक्त कला प्रदर्शनी "चित्रायण: जर्नी थ्रू आर्ट" प्रदर्शित की गई है।

मुख्यमंत्री ने किसान हित में लिया निर्णय

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय किया है। अब पीएम कुसुम योजना के तहत स्थापित विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्रों से जुड़े 33/11 केवी सब स्टेशन क्षेत्रों में अलग से प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कृषि कनेक्शन जारी किए जा सकेंगे। इसके लिए कृषि कनेक्शन नीति-2017 में संशोधन को भी मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश के तीनों विद्युत वितरण निगमों ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

मुख्यमंत्री के इस निर्णय के पश्चात अब ऐसे सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता के अनुसार 33/11 केवी से निकलने वाले फीडरों पर कृषि कनेक्शन के लिए आवेदकों को पृथक से प्राथमिकता से मांग पत्र जारी किए जा सकेंगे। मांग पत्र जमा होने के बाद आवेदकों को तुरंत प्राथमिकता से कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे।

मौजूदा समय में कृषि कनेक्शन नीति-2017 के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन के आवेदकों को राज्य सरकार द्वारा घोषित निर्धारित अंतिम तिथि (कट ऑफ डेट) के अनुसार डिमांड नोट जारी किए जाते हैं। मांग पत्र जमा होने के बाद कनेक्शन जारी करने की प्राथमिकता मूल आवेदन तिथि के अनुसार संधारित की जाती है। वहीं अन्य श्रेणी-डिप, डिग्गी अथवा शहरी क्षेत्र के आवेदकों के मांग पत्र तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर जारी किए जाते हैं। इन आवेदकों के लिए कनेक्शन जारी करने की प्राथमिकता मांग पत्र जमा करवाने की तिथि के अनुसार संधारित की जाती है।

वर्तमान में 22 फरवरी 2022 तक की कट ऑफ डेट के अनुसार सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कनेक्शन देय हैं। राज्य में फिलहाल 78 हजार 498 कृषि कनेक्शन लंबित हैं, जिनमें डिमाण्ड नोट जमा किए जा चुके हैं।

> ■ विकेन्द्रित सौर संयंत्रों से संबद्ध फीडरों में तुरन्त जारी होंगे कृषि कनेक्शन